IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में कृषि विपणन पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव

नाम – दुर्गा कुमारी
शोधार्थी – वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा

सारांश :– भारतीय कृषि के सामने न सिर्फ अपने मामले में बल्कि एक कुशल स्तर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को उठाने पर लक्षित व्यापार, विनिर्माण करने का संबंध है और वित्तीय सेवाओ ने उद्योगों के साथ जगह ले ली है कि सुधारों की श्रृंखला। कृषि की इस नए मॉडल को समान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना जाता है । इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना था। किसानें के हितों का ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही सरकार ने कृषि उपज को विपणन व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। मण्डियों में व्याप्त कपटपूर्ण पद्धतियों पर रोक लगायी है, भंडार गृहों की स्थापना की है, मध्यस्थों में कमी कर मूल्यों को नियंत्रित किया है। इन सबके बावजूद वर्तमान कें कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में दोष व्याप्त है। इस अध्याय मे बिहार में कृषि विपणन पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव का विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा।

परिचय

1980 के दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल, एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्धेश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना था। एक अधिक कुशक स्तर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को अठाने पर लक्षित व्यापार विनिर्माण करने का संबंध है और वित्तीय सेवाओं ने उद्योग के साथ जगह ले ली है कि सुधारों की श्रृंखला। इन आर्थिक सुधारों को एक महत्वपूर्ण तरीके से देश के समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित किया था।

एलपीजी और भारत के आर्थिक सुधार नीति

15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य समाजवादी आर्थिक रणनीतियों के लिए अटक गया। 1980 के दशक में राजीव गांधी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आर्थिक पुनर्गठन उपायों के एक नंबर से शुरू कर दियां 1991 में देश के खाड़ी युद्ध और तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद भुगतान दुविधा की एक संतुलन का अनुभव किया। देश स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोने की 47 टन की राशि जमा करने के लिए किया था। इस आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक वसूली संधि के तहत जरूरी हो गया था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थित आर्थिक पुर्नसंगठन के एक दृश्य की एक कल्पना करने के भारत जरूरी हो।

डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तब भारत सरकार के वित्त मंत्री थे। उन्होने कहा कि सहायता प्रदान की। नरसिंह राव और इन सुधार की नीतियों के लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नरसिंह राव समिति की सिफारिशें

इस प्रकार के रूप नरसिंह राव समिति की सिफारिशों पर किए गए

सुरक्षा नियमों में लाना संशोधित रिकार्ड और पूंजी बाजार में सभी मध्यस्थों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैध शक्ति प्रदान की गई है जो 1992 के सेबी अधिनिय। दरों और कंपनियों के बाजार में जारी करने वाले थे कि शेयरों की संख्या निर्धारित किया है कि 1992 में राजधानी मामलों के नियंत्रक के साथ दूर कर रहा है। देश के अन्य शेयर बाजारों के पुनर्गठन को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण के रूप में 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शुभारंभ। वर्ष 1996 तक नेशनल स्टाक एक्सचेंज का भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार के रूप में सामने आया था।

1992 में देश के शेयर बाजारों में विदेशी कॉर्पोरेट निवेशकों के माध्यम से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया था। कंपनियों के जीडीआर या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने के माध्यम से विदेशी बाजारों से धन जुटाने की अनुमति दी गई। 40 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करने के लिए व्यापार के कारोबार या साझेदारी मे अंतरराष्ट्रीय पूंजी के योगदान पर उच्चतम सीमा बढ़ाने के माध्यम से एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 फीसदी इंटरनेशनल इक्विटी अनुमति दी गई थी। 25 प्रतिशत करने के लिए 85 प्रतिशत का एक मतलब स्तर से शुल्क घटाए जाने और मात्रात्मक नियमों को वापस लेने। रूपया या अधिकारी भारतीय मुद्रा व्यापार खाते पर एक विनिमेय मुद्रा में बदल गया था। 35 क्षेत्रों में एफडीआई की मंजूरी के लिए तरीकों के पुनर्गठन। अंतरराष्ट्रीय निवेश और भागीदारी के लिए सीमाओं का सीमांकन किया गया। इन पुर्नसंगठन के परिणाम विदेशी निवेश की कुल राशि एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश शामिल है नरसिंह राव उत्पादन क्षेत्रों के साथ औद्योगिक दिशा निर्देश परिवर्तन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस की आवश्यकता है जो सिर्फ 18 सेक्टरों को छोड़ने तथा दूर लाइसेंस के साथ किया था। उद्योगों पर नियंत्रण संचालित किया गया था।

नीति की मुख्य विशेषताएं

उदारीकरण भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर प्रकाश डाला जो नीचे दिए गए हैं:–

1. विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते
2. विदेशी निवेश
3. एमआरटीपी अधिनियम 1969 संशोधित
4. औद्यौगिक लाइसेंसिंग में ढ़ील
5. निजीकरण की सामूहिक चर्चा
6. विदेशी व्यापार के लिए अवसर
7. मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए कदम कर सुधारों
8. लाइसेंस पार्मिट् राज के उन्मूलन

आर्थिक माहौल को भी कारोबारी माहौल कहा जाता है और दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हमारे देश की आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कुछ उद्योगों, केंद्रीय योजना के राज्य द्वारा नियंत्रण और निजी क्षेत्र की कम महत्व सहित कई कदम उठाए हैं। तदनुसार इस भारत के विकास की योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे।

1. जीवन स्तर को बढ़ाने में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबी भूमि पीछा कम करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास का आरंभ।
2. आत्मनिर्भर बनें और भारी बुनियादी उद्योगों पर जोर देने के साथ एक मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित।
3. देश भर में उद्योगों की स्थापना से संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त।
4. आय और धन की असमानताओं को कम।
5. समानता पर आधारित है और आदमी द्वारा मनुष्य के शोषण को राकने के विकास का एक समाजवादी पैटर्न अपनाने।

ध्यान में रखते हुए उक्त उद्देश्यों के साथ आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में एक नई औद्यौगिक नीति की धोषणा की।

इस प्रकार इस नीति के व्यापक सुविधाए थें

1. सरकार केवल छह के लिए अनिवार्य लाइसेंस के तहत उद्योगों की संख्या कम हो।
2. विनिवेश कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्यौगिक उद्यमों के मामले में किया गया।
3. नीति को उदार बनाया गया था। विदेशी इक्विटी भागीदारी की हिस्सेदारी बढ़ गया था और कई गतिविधियों में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी थी।
4. स्वत अनुमति बव विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्यौगिकी समझौतों के लिए प्रदान किया गया था।
5. विदेशी निवेश संवर्धान बोर्ड एुआईपीबी को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी निवेश छनेलिज़े करने के लिए स्थापित किया गया था।

उदारीकरण

उदारीकरण सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। भारत में आर्थिक उदारीकाण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ जो जारी रखने के वित्तीय सुधारों को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित विशेषताएं समाहित हैं

1. उदारीकरण सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध से भारतीय व्यापार और उद्योग को उदार बनाने के उद्देश्य से किया गया।
2. वे लाइसेंस परमिट कोटा राज के अंत का संकेत है।

भारतीय उद्योग ने उदारीकरण के लिए सम्मान के साथ जगह ले ली है

1) एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर उद्योगों में अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता खत्म।
2) व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
3) व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने तय करने में द्वितीय स्वतंत्रता।
4) वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने में स्वतंत्रता।
5) अर्थव्यवस्था पर कर की दरों में कमी और अनावश्यक नियंत्रण के उठाने।
6) आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और
7) यह आसान भारतीयों के लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्यौगिकी को आकर्षित करने के लिए बना।

निजीकरण

निजीकरण के रूप में अच्छी तरह से निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार से स्वामित्व के हस्तांतरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता है।

निजीकरण निम्न सुविधाओं की विशेषता थी

1. राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक कम भूमिका को बड़ी भूमिका देने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों के नए सेट का निर्माण किया गया।
2. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार 1991 की नई औद्यौगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को नई परिभाषा दी।
3. उसी के उद्देश्य सरकार के अनुसार वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किया गया था।
4. यह भी निजी पूंजी और प्रबंधकीय क्षमताओं को प्रभावी ढ़ंग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि मनाया गया।
5. सरकार ने यह भी प्रंधकीय नर्णय लेने में उन्हें स्वायत्तता देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया गया है।

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण की दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के समेकन के लिए खड़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के निम्नलिखित विशेषताएं हैः–

- वैश्वीकरण पहले से ही सरकार द्वारा शुरू किए गए उदारकरण और निजीकरण की नितियों का नतीजा है।
- वैश्वीकरण आम तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण का मतलब यह समझा जाता है । यह समझने के लिए और व्यवहार में लागू करने के लिए एक जटिल घटना है।
- यह अधिक से अधिक निर्भरता और एकीकरण की दिशा में दुनिया को बदलने के उद्देश्य से कर रहे है कि विभिन्न नीतियों के सेट का नतीजा है।
- यह आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है।
- वैश्वीकरण वैश्वीक अर्थव्यवस्था के विभिन्न राष्ट्रों के बीच बातचीत और परस्पर निर्भरता का एक बढ़ा स्तर शामिल है।
- शारीरिक भौगोलिक अंतर या राजनीतिक सीमाओं नहीं रह गया है दुनिया भर में एक दूर के भौगोलिक बाजार में एक ग्राहक सेवा करने के लिए एक व्यावसायिक उद्यम के लिए बाधाओं रहते हैं।

भारत में आर्थिक सुधार

ऐतिहासिक रूप से लम्बे समय तक भारत एक बहुत विकसित आर्थिक व्यवस्था थी जिसके विश्व के अन्य भागों के साथ मजबूत व्यापारिक सम्बन्ध थे। औपनिवेशिक युग 1773 से 1947 के दौरान अंग्रेज भारत से सस्ती दरों पर कच्ची सामग्री खरीद करते थे और तैयार माल भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कहीं अधिक उच्चतर कीमत पर बेचा जाता था जिसके परिणामस्वरूप स्रोतों का बहुत अधिक द्विमार्गी ह्रास होता था। इस अवधि के दौरान विश्व की आय में भारत का हिस्सा 1700 ईस्वी के 223 प्रतिशत से गिरकर 1952 में 38 प्रतिशत रह गया। 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अर्थव्यवस्था की पुर्ननिर्माण प्रकिया प्रारंभ हुई। इस उद्देश्य से विभिन्न नीतियाँ और योजनाएँ बनाई गयीं और पंचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से कार्यान्वित की गयी।

भारत में 1980 तक जीएनपी की विकास दर कम थी, लेकिन 1981 में आर्थिक सुधारों के शुरू होने के साथ ही इसने गति पकड़ ली थी। 1991 में सुधार पूरी तरह से लागू होने के बाद तो यह मजबूत हो गई थी। 1950 से 1980 के तीन दशकों में जीएनपी की विकास दर केवल 1.49 फीसदी थी। इस कालखंड में सरकारी नीतियों का आधार समाजवाद था। आयकर की दर में 97.75 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गयी। कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण के प्रयास और अधिक तेज कर दिए थे। 1980 के दशक में हल्के से आर्थिक उदारवाद ने प्रति व्यक्ति जीएनपी की विकास दर को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2.89 कर दिया। 1990 के दशक में अच्छे खासे आर्थिक उदारवाद के बाद तो प्रति व्यक्ति जीएनपी बढ़कर 4.19 फीसदी तक पहुंच गई। 2001 में यह 6.78 फीसदी तक पहुंच गई। 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए जो इस दृष्टि से वृहद प्रयासरत थे कि इनमें विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। इन उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल आई है।

सकल स्वदेशी उत्पाद की औसत वृद्धि फैक्टर लागत पर जो 1951–91 के दौरान 6.24 प्रतिशत के रूप में बढ़ गयी। 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गयी।

आर्थिक सुधार की दिशा में 1991 से अब तक उठाये गये कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं.

- औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति
- आयात शुल्क में कमी लाना तथा मात्रात्म तरीकों को चरणबद्ध
- बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं
- वित्तीय क्षेत्र में सुधार
- पूँजी बाजार का उदारीकरण
- सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश
- निजीकरण
- उत्पाद शुल्क में कमी
- आयकर तथा निगम कर में कमी
- सेवा कर की शुरूआत
- शहरी सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवें स्थान पर है। जनसंख्या में इसका पहला स्थान है और केवल 2.4 क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17 भाग को शरण प्रदान करता है। 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण का बोलबाला था और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ परन्तु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम हुआ है। हालाँकि मूलभूत ढ़ाँचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका अब भी नाखुश है और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुये हैं। 2014 में 4.6 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गई। लगातार दो वर्षों तक 5 प्रतिशत से कम की स.घ.उ. विकास दर अंतिम बार 25 वर्ष पहले 1986–87 और 1987–88 में देखी गई थी।

सकल घरेलू उत्पाद

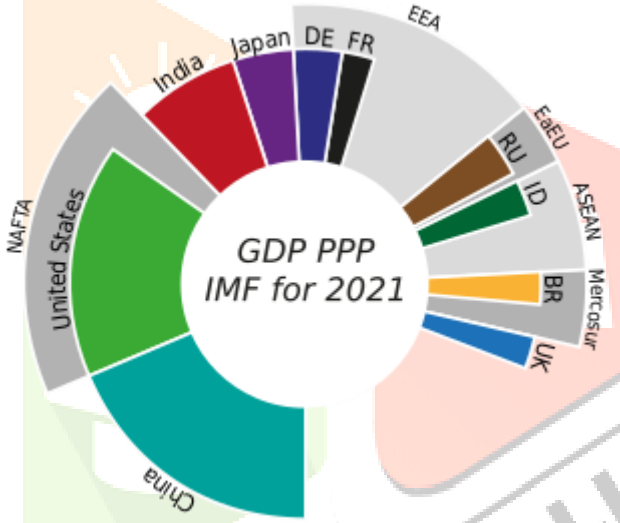

2013–14 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद भारतीय रूपयों में 113550.73 अरब रूपये था।

आंकड़ा श्रेणियां	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
स0घ0उ0 रू करोड़ वर्तमान बाजार मूल्य	6477827	7784115	9009722	10113281	11355073
वृद्धि दर	15.1	20.2	15.7	12.2	12.3
स.घ.उ. रू करोड़ घटक लागत 2004–05 के मूल्य पर	4516071	4918533	5247530	5482111	5741791
वृद्धि दर	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय मौजूदा कीमतों पर उत्पादन लागत	46249	54021	61855	67839	4380

लॉकडाउन अथर्व्यवस्था प्रभाव

अपैल–दिसम्बर 2021 तक की अवधि में भारत से वस्तुओं एवे सेवाओं के हुए निर्यात के वास्तविक आंकड़ों को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत से वस्तुओं का निर्यात 75,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार हो जाने की प्रबल सम्भावना है। जिस गति से वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात बढ़ रहे हैं उससे अब यह माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 100,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है जो कि अपने आप में एक इतिहास रच देगा।

निष्कर्ष

विदित है कि भारत में बड़ी कृषक आबादी निवास करती है। यदि यह क्षेत्र समस्याग्रस्त बना रहेगा तो भारत में पहले से ही मौजूद आर्थिक असमानता में और भी वृद्धि होगी तथा कृषि विपणन पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव समग्र मांग में भी कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में कृषि सुधार के लिये सरकारों द्वारा गंभीर प्रयास देखने को नहीं मिले है। अतीत में भूमि सुधार कृषि सुधार अधिनियम इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब समय की मांग है कि सरकारें इस क्षेत्र को भी कृषि विपणन पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव गंभीरता से लें तथा एक ऐसी व्यापक रणनीति के आधार पर सुधारों को लागू करने का प्रयास करें जिससे इस क्षेत्र में ढ़ाँचागत परिवर्तन लाया जा सके।

सन्दर्भ

- प्रति व्यक्ति आय पत्र सूचना कार्यालए भारत सरकार 25 जुलाई 2014 मूल से 11 जुलाई 2018 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 28 जुलाई 2014.
- आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति वित्त मंत्रालय भारत सरकार जुलाई 2014 मूल से 14 जुलाई 2014 को पुरालेखित अभिगमन तिथि जुलाई 2014 में तिथि प्राचल का मान जाँचे मदद।
- भारत बना दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी इकॉनमी नवभारत टाईम्स 30 अप्रैल 2014 मूल से 2 मई 2014 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 30 अप्रैल 2014.
- फ्रांस को पछाड़कर भारत दुनिया की पाँचवा बड़ी अर्थव्यवस्था बना मूल से 25 सितंबर 2020 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 11 जुलाई 2018.
- दकपं इमबवउमे वूतसकशे पेगजी संतहमेज मबवदवउलए उनेबसमे चेंज थ्तंदबम मूल से 9 अगस्त 2018 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 11 जुलाई 2018.
- अंगस मैडिसन द वर्ड इकनॉमी अ इलेनिअल परस्पेक्टिव।
- रंगराजन सी0 सीमा और ई0 एम0 विबीश 2014 डेवल्पमेंट्स इन दि वर्कफोर्स बिटवीन 2009–10 एंड 2011–12 इकनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली वाल्यूम।
- केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक सीजीए।
- राजसहायता में कमी पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार 11 जुलाई 2014 मूल से 14 जुलाई 2014 को पुरालेखित अभिगमन तिथी 12 जुलाई 2014 द्यकंजमत्र में तिथि प्राचल का मान जाँचें मदद
- भारत एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात की ओर अग्रसर बनेगा इतिहास
- जनलवा समाजवाद स्वामीनाथन एस अय्यर मूल से 4 जुलाई 2015 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 3 जुलाई 2015.